आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 24.04.2023 से 29.04.2023)

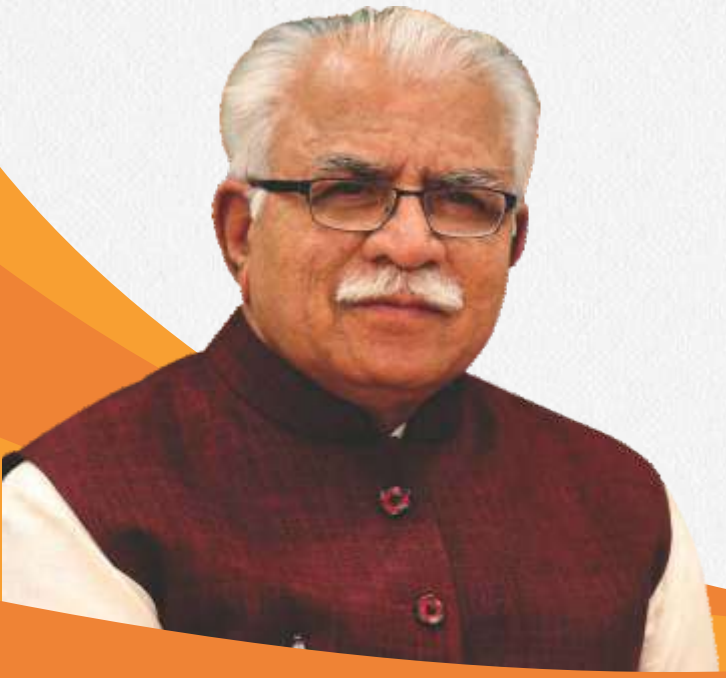

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय राष्ट्रपति जी का हरियाणा दौरा

(दिनांक 24.04.2023)

प्रभाव : माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपने हरियाणा दौरे के दौरान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और 544 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। एनडीआरआई देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। आज पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में जिस मुकाम पर देश खड़ा है, उससे हम दुनिया के सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले देश बने हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की कल्पना के बिना

पशुपालन व मत्स्य संभव नहीं है। जब कृषि की बात होती है तो पशुपालन स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ा ही रहता है। जब देश भर में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विश्वविद्यालयों और आईसीआर के विश्वविद्यालयों में एनडीआरआई ने लगातार 5 वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

उन्होंने कहा कि एनडीआरआई के प्रयासों के परिणामस्वरूप 2021 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति 444 ग्राम दूध की उपलब्धता है। वर्ष 2013–14 से लेकर आज तक अधिक वृद्धि को देखते हैं तो यह 44 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य और संस्थान की उज्जवल यात्रा के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के 25वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना। राष्ट्रपति जी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के 25वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विद्यार्थियों को डिग्रियां व गोल्ड मेडल प्रदान कर कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान करते हुए कहा कि आज कृषि के समक्ष

बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ती कृषि भूमि, गिरते भूजल–स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता, जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक चिंताएं हैं, जिनका समाधान खोजना कृषि पेशेवरों, वैज्ञानिकों का दायित्व है। आज ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हमारी विशाल जनसंख्या को पर्यावरण और जैव–विविधता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में आधे से अधिक बेटियों की संख्या से गौरवान्वित हुई माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 70 प्रतिशत से अधिक छात्राएं हैं। यह संतोष और गर्व का विषय है कि हमारी बेटियां कृषि एवं संबंद्ध विज्ञान सहित अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन

का एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन आज शिक्षा संपूर्ण नहीं हुई है, केवल एक हिस्सा पूरा हुआ है। आपको अपने ज्ञान और क्षमताओं के विस्तार के लिए दुनिया भर के नवीनतम नवाचारों से अवगत रहना होगा। आपका यह प्रयास देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाने में सार्थक होगा।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अपने स्थापना के समय से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता में भी इस विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पानी कृषि का एक अहम घटक है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जल का मितव्ययता के साथ उपयोग किया जाए। इन दोनो ही अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी महामहीम राष्ट्रपती जी के साथ उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवा वैज्ञानिक अपनी उपलब्धियों से कृषि विश्वविद्यालय के साथ–साथ हरियाणा का नाम देश–विदेश में रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षार्थ आईए सेवार्थ जाइये वाली कहावत को चरितार्थ करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को समाज सेवा में लगाकर बेहतर प्रमाण देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी युवा वैज्ञानिकों को बधाई देता हुए कहा कि किसानों के लिए फसल विविधिकरण

के साथ–साथ डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक कीटनाशक व जल संरक्षण पद्धतियों को भी बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देश–विदेश में बड़ा नाम कमाया है और यही नहीं आज हरियाणाा प्रदेश जिस समृद्धि और खुशहाली के मुकाम पर पहुंचा है उसमें इस विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय योगदान है। इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किये गये बीजों, खेती की आधुनिक तकनीकों आदि को अपनाकर हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भण्डार भरे हैं।

कृषि विश्वविद्यालय का नाम किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया। वे देश की खुशहाली के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के पक्षधर थे। उन्होंने ही वर्ष 1979 में देश के उप–प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की थी, जो आज ग्रामीण विकास की धुरी बन चुका है।

हरित क्रांति से आत्मनिर्भर होने के साथ–2 कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। परम्परागत खेती के कारण पानी का अधिक दोहन हुआ जिसके कारण कई क्षेत्र डार्क जोन भी हो गए। इसलिए चुनौतियों पर काबू पानी के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है।

उन्होने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ जय पहलवान कहें और देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने महाराण प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही नए एक्सीलेंट सेंटर खोलने का कार्य किया है। इसके अलावा हरियाणा में धान जैसी ज्यादा पानी से उगने वाली फसल के स्थान पर कम पानी से उगने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा पानी–मेरी विरासत योजना' चलाई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम में कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करना

(दिनांक 05.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गुरुग्राम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट वार्ता को संबोधित कर कहा कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के साथ–साथ उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के साथ–साथ अब निजी क्षेत्र को उनकी आवश्यकता अनुरूप श्रम शक्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा सरकार की इस पहल से कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी जरूरतों के हिसाब से वर्कफोर्स मिलने की राह आसान बनेगी। माननीय

साप्ताहिक सूचना पत्र

मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किल इंडिया विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के युवाओं के कौशल विकास की जो दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई थी, हमने हरियाणा में उस विजन को मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है।

इसके तहत पलवल के दूधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य कौशल विकास प्राधिकरण भी स्थापित किया गया है। युवाओं के कौशल विकास के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी अनेक पहल की गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर प्रदेश के करीब आठ लाख युवा पंजीकृत है।

निजी क्षेत्र अपनी श्रम शक्ति की जरूरतों को इस पोर्टल के माध्यम से पूरा कर सकता है। उन्होने कहा कि पदमा योजना के तहत हर ब्लाक में कलस्अर बनाए जाएंगे जिसके तहत एमएसएमई क्षेत्र में 14 हजार ईकायों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साढे

तीन लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने बताया कि एचकेआरएनएल के माध्यम से कॉरपोरेट जगत को स्किल्ड, अन स्किल्ड व मैनेजमेंट आदि श्रेणियों में पंजीकृत युवाओं का डेटा शेयर किया जाएगा।

इस डेटा में विशेषता यह रहेगी कि इंडस्ट्री अपनी आवश्यकता के जितने भी मानक जैसे संख्या, शिक्षा, अनुभव आदि तय करेगी उसी अनुरूप डेटा उपलब्ध होगा। साथ ही श्रमशक्ति के लिए निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवार उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि निजी क्षेत्र स्वयं इंटरव्यू लेकर चयन कर सके।

उन्होंने कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से हरियाणा में आय के आधार पर परिवारों का डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में 13 लाख परिवार ऐसे है जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम है और 29

लाख परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए से कम है। इन परिवारों को स्वरोजगार, सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दृष्टिकोण की वार्ता में पहुंचे कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने सराहना की। रिलांयस एमईटी, मारूति सुजुकी, एलएमएल ग्रुप, एसोचौम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, राई आदि क्षेत्रों की विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी वर्कफोर्स की जरुरतों के लिए एचकेआरएनएल के डेटा से पूरा करना का भरोसा दिया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

दो कंपनियों ने दिया हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट में चार करोड़ रूपये से अधिक का योगदान

(दिनांक 25.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी को दो कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सीएसआर फंड के तहत चार करोड़ रुपए व 61 लाख 06 हजार के चेक सौंपे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट को मिली इस धनराशि का उपयोग प्रदेश में तालाबों के पुनरूद्घार व लाइब्रेरी खोलने में किया जाएगा। उन्होनें कहा इंडस टावर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने चार करोड़ रुपए तथा पेरनो रिकॉर्ड इंडिया द्वारा 61 लाख 06 हजार रुपए धनराशि का चेक दिया।

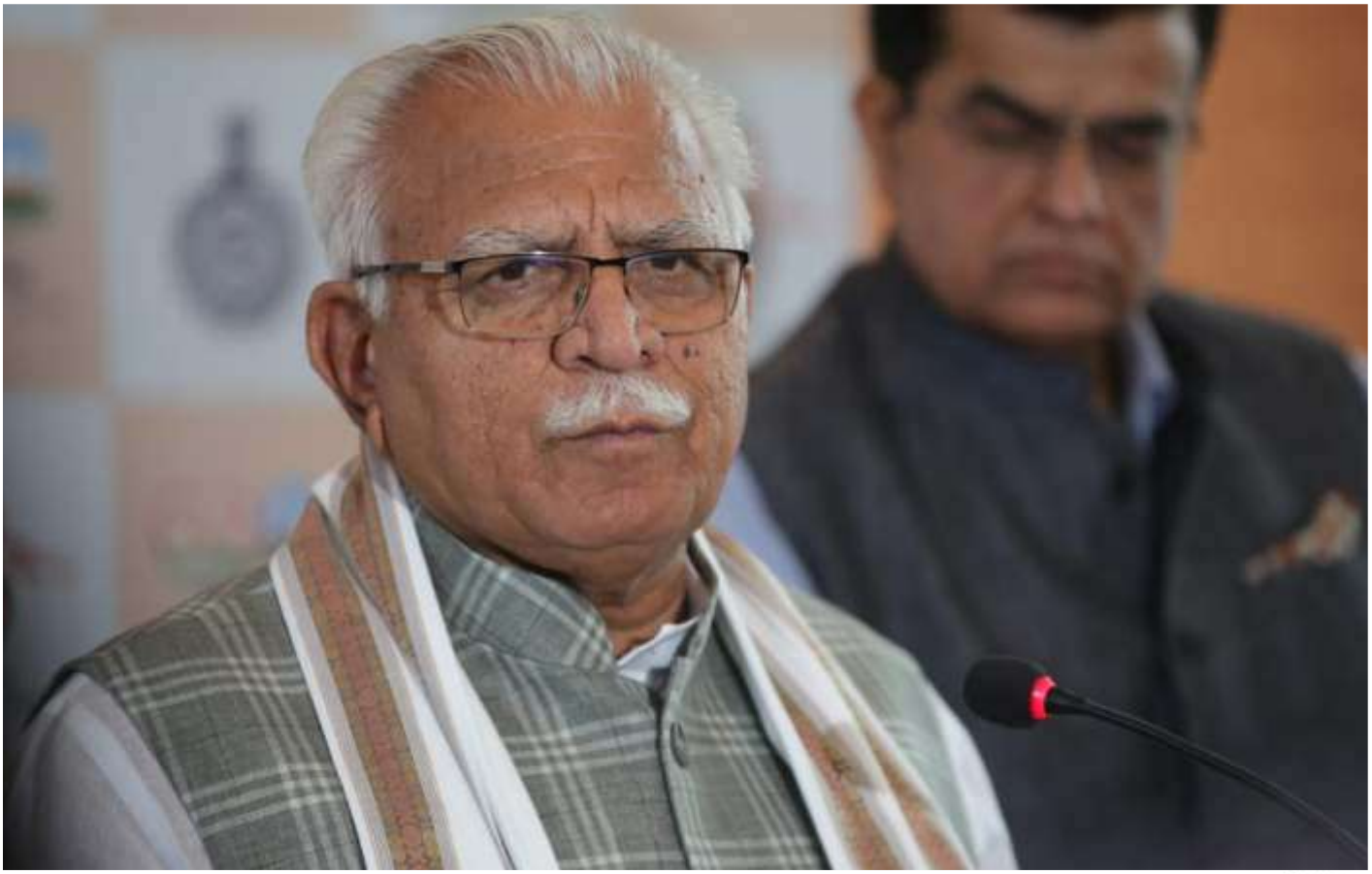

साप्ताहिक सूचना पत्र

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 (एनसीएफ) को लेकर अहम बैठक का आयोजन

(दिनांक 26.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 (एनसीएफ) को लेकर एक अहम बैठक की । उन्होनें कहा कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही ज्ञानवान बनने के साथ साथ संस्कारवान भी बनें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्कूली पाठ्यक्रम को देखा और अधिकारियों से किस–किस विषय के लिए कितना समय सुनिश्चित किया जाए, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा की, ताकि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुसार बच्चों का चरित्र निर्माण भी किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने तथा ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पीएम–श्री योजना के तहत प्रदेश में पीएम–श्री स्कूल स्थापित करने की दिशा में भी कार्य योजना तैयार कर जल्द उसे क्रियान्वित किया जाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पांच एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए कार्य कर रही है।

राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। आज हरियाणा शिक्षा क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अमृत जल क्रांति संगोष्ठी कार्यक्रम

(दिनांक 26.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी–अमृत जल क्रांति के पहले दिन के समापन सत्र में बोलते हुए नागरिकों से आह्वान किया कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति हेतू जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाले पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के

साथ–साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा।

संयोग से यह संगोष्ठी उस समय हो रही है, जब किसानों के मसीहा और उनकी चिंता करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। वे सदैव किसानों की बात करते। ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए यह जल संगोष्ठी उन्हें समर्पित है। हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्त्रोत नहीं, पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। हरियाणा में केवल वर्षा का पानी और पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पर प्रवाहित होने वाला पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि यदि पानी के उपयोग के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा हितधारक किसान है, क्योंकि अधिकांश पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, उद्योगों तथा घरों में भी पीने के अलावा अन्य कार्यों में पानी की अधिकतर खपत होती है। लेकिन पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। आज प्रदेश के 85 ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं।

पिछले 8 सालों में राज्य सरकार द्वारा जल सरंक्षण के लिए विभिन्न योजनाए बनाई गई है जिसकी सराहना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथ अन्य संस्थाओं द्वारा भी समय–समय पर की गई है। लगभग 2500 करोड़ रूपये की लागत से वेस्टर्न जमुना कनाल को मजबूत किया गया है जिसका कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा इससे पानी की बचज भी होगी और पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। पानी की मांग और उपलब्धता के अंतराल को पूरा करने के लिए वर्षा के पानी का संग्रह करने के सिस्टम खड़े करने होंगे। इसके अलावा, रिजरवायर, तालाबों और झीलों की क्षमताएं बढ़ानी होगी तथा भूजल रिचार्जिंग पर भी काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आज भूजल रिचार्ज से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के

संग्रह के साथ–साथ उसके प्रबंधन के लिए काम करने की आवश्यकता है और वर्तमान समय में पानी की मांग को पूरा करने के लिए थ्री–आर यानी रिड्यूस, रीसाइकिल और रीयूज की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए अधिक से अधिक ट्रीटेड वाटर का उपयोग करना होगा। ट्रीटेड वॉटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 200 एसटीपी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से लगभग 1800 एमएलडी पानी का उपयोग किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर ट्रीटेड वाटर पीने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जबकि हम अभी सिंचाई तथा अन्य उपयोगों के लिए ही ट्रीटेड वॉटर का उपयोग कर रहे हैं। पानी की आपूर्ति, इसके प्रबंधन तथा पानी की चोरी रोकने के लिए आरटीडास सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अब तक 180 आरटीडास लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा भूजल की गहराई का पता लगाने के लिए 1700 पिजोमीटर लगाए जा चुके हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

समापन सत्र के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पानी को बचाने व सिंचाई में पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए जिसपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को संबंधित सुझावों का विस्तार से अध्ययन कर नई योजना बनाने तथा पायलट प्रोजेक्ट लगाने के निर्देश दिए।

जल संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र में जल संरक्षण की दिशा में कदम आगे बढाते हुए सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ करने की घोषणा की। इससे 218 एम.सी.एम. पानी की बचत होगी। इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी की का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की कि अगले दो वर्षों में 9500 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें 5308 तालाब, 63 चौक डैम, 81 उथले ट्यूबवैल और 4000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं।

प्राकृतिक खेती के तहत 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करके इसके अधीन 6,000 एकड़ क्षेत्र से 25 हजार एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। राज्य सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि के सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसकी प्राप्ति के लिए कार्य में तेजी लाने के लिए कृषि विभाग केन्द्रीय लवणीय मृदा सुधार संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा और अगले तीन महीनों में अपनी कार्य

योजना को अंतिम रूप देगा। इस कार्य के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वह भी किया जाएगा।

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व बैंक ने अटल भुजल योजना का राज्य के 14 जिलों में विस्तार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले चरण में पंचवर्षीय योजना के तहत 700 करोड़ों का बजट मिला था। दूसरे चरण में भी विश्व बैंक की ओर से लगभग 700 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाएगा। इससे राज्य का जल भराव का 90 प्रतिशत क्षेत्र कवर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में पानी की 50 प्रतिशत मांग को एस.टी.पी. के ट्रीटेड वेस्ट वाटर द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि की जरूरतों के लिए 75 एस.टी.पी. के पानी का उपयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगले दो वर्षों में 31 एचएसआईआईडीसी सम्पदाओं में से 18 में उपचारित अपशिष्ट जल का शत–प्रतिशत पुनः उपयोग किया जाएगा। एसटीपी का 50 फीसदी ही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम 100 फीसदी तक लेकर जाएंगे।

पानी का बड़ा उपयोग उद्योग क्षेत्र में भी होता है इसलिए सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है जिसके तहत आईएमटी सोहना, आईएमटी खरखौदा और ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेड.एल.डी.) लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के तहत भी क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। अभी 2500 एकड़ में मत्स्य पालन किया जा रहा है जिसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करेगा। आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर के उपयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

साप्ताहिक सूचना पत्र

ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन

(दिनांक 28.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन (ओपनिंग सेरेमनी) अवसर पर वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में जब पूरा संसार युद्ध, आतंकवाद, हिंसा व तनाव का सामना कर रहा है, इस समय गीता में दिया गया विश्व शांति, प्रेम और भाईचारा का संदेश हर मानव के लिए वर्तमान समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीयों विशेषकर हरियाणावासियों के लिए यह गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की स्वयंसेवी संस्थाओं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया की पावन धरा पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सहयोग करने वाली सभी संस्थाओं का हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने कहा कि

गीता एक ऐसा अलौकिक प्रकाश पुंज है, जो काल, देश और सीमाओं से परे है, जो सर्वकालिक, सार्वभौमिक और चिरस्थायी है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि श्रीमद्भगवद्गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए सार्थक है। उनके मार्गदर्शन से हरियाणा सरकार गीता के इस ज्ञान को दुनिया के कोने–कोने

साप्ताहिक सूचना पत्र

तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। प्रतिनिधिमंडल में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, पानीपत से विधायक महिपाल ढांडा शामिल हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं महान भारत के उस छोटे से प्रदेश हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ जहाँ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्रीकृष्ण ने 5160 वर्ष पहले गीता के माध्यम से कर्म योग का अमर संदेश दिया था, जो सदियों तक मानव का मार्गदर्शन करता रहेगा।

उन्होंने इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने गीता के प्रति जो आस्था एवं श्रद्धा और उत्साह दिखाया है, उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।

उन्होंने गीता की पावन भूमि कुरूक्षेत्र आने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक में कहा गया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने यह भी संदेश दिया है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा में निहीत है। गीता का यह संदेश यदि विश्व के सभी लोग समझ लें तो फिर सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सारा संसार एक परिवार हो जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

नूहं में साइबर फ्रॉड पर हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन

(दिनांक 28.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा अपराध को जड़ से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नूहं जिले में पैर पसार रहे साइबर क्राइम के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की अलग–अलग टीमों ने कल देर रात एक साथ नूहं जिले के 14 गावों में छापेमारी कर 125 हैकर व साइबर अपराधियों को काबू किया।

इनके पास से अलग–अलग बैंक के एटीएम, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, आधारकार्ड और एटीएम स्वैप मशीन के साथ ही अन्य सामान बरामद किया गया है। इन संदिग्धों को काबू कर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले बीते कुछ दिनों में पुलिस को नूंह जिले के अलग–अलग क्षेत्रों में साइबर फ्रॉड से संबंधित इनपुट मिले थे। एक कमरे में बैठे–बैठे कुछ लोग दूसरों के बैंक खातों को साफ कर दिया करते थे। मिले इनपुट के आधार पर साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट एरिया को चिन्हित कर इन ठिकानों पर भारी पुलिसबल के साथ एक साथ रेड की गई। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए हरियाणा पुलिस ने 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों की अलग–अलग टीमें गठित की जिसमें एक एसपी, 6 एडिशन एसपी, 14 डीएसपी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराध के खिलाफ अभियान छेड़ा।

साइबर ठगों पर यह कार्रवाई पुलिस की विभिन्न जिलों की गठित की गई 102 रेडिग टीमों द्वारा की गई। पुलिस की अलग–अलग टीमों ने एक साथ पुन्हाना, पिनंगवा, फिरोजपुर झिरका,

साप्ताहिक सूचना पत्र

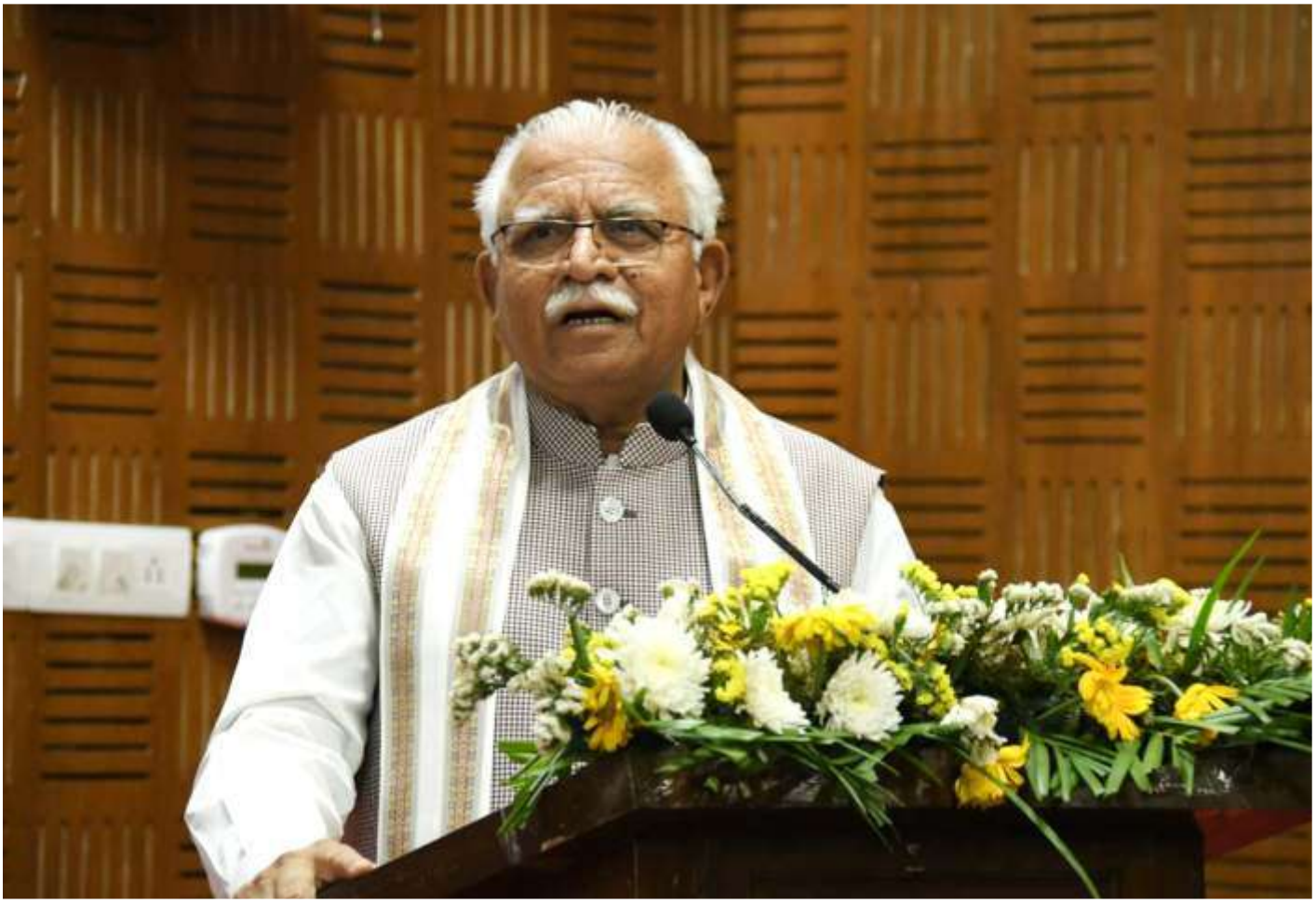

बिछौर एरिया के 14 चिन्हित गावों में छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला नूहं में पुलिस द्वारा 8 अप्रैल के बाद से साइबर ठगी के मामलों से संलिप्त 20 अपराधियों को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है।

पुलिस ने इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम और अन्य उपकरण के साथ ही नकदी भी बरामद की है। साथी ही, 10,000 रुपये के एक इनामी अपराधी को भी काबू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा सख्ती से कदम उठाने के साथ–साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद

(दिनांक 28.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोक सभा के प्रबुद्घ लोगों के साथ चार घंटे से अधिक समय तक संवाद कर प्रमुख लोगों से हल्के सम्बन्धी कार्यों व नई प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अम्बाला लोक सभा क्षेत्र के प्रबुद्घ लोगों के साथ संवाद किया और कार्यों की फीडबैक ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रबुद्घ नागरिकों का दायित्व है कि वे सरकार की योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के साथ–साथ लाभार्थी को सीधा लाभ मिले, यह सुनिश्चित करे, इसके अलावा, योजनाओं की निगरानी भी करे ताकि किसी भी प्रकार की देरी व भष्टड्डाचार न हो। विकास कार्यों में जनभागीता जरूरी है और इलाके मांग के अनुसार ही प्रस्ताव भेजे जाएं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

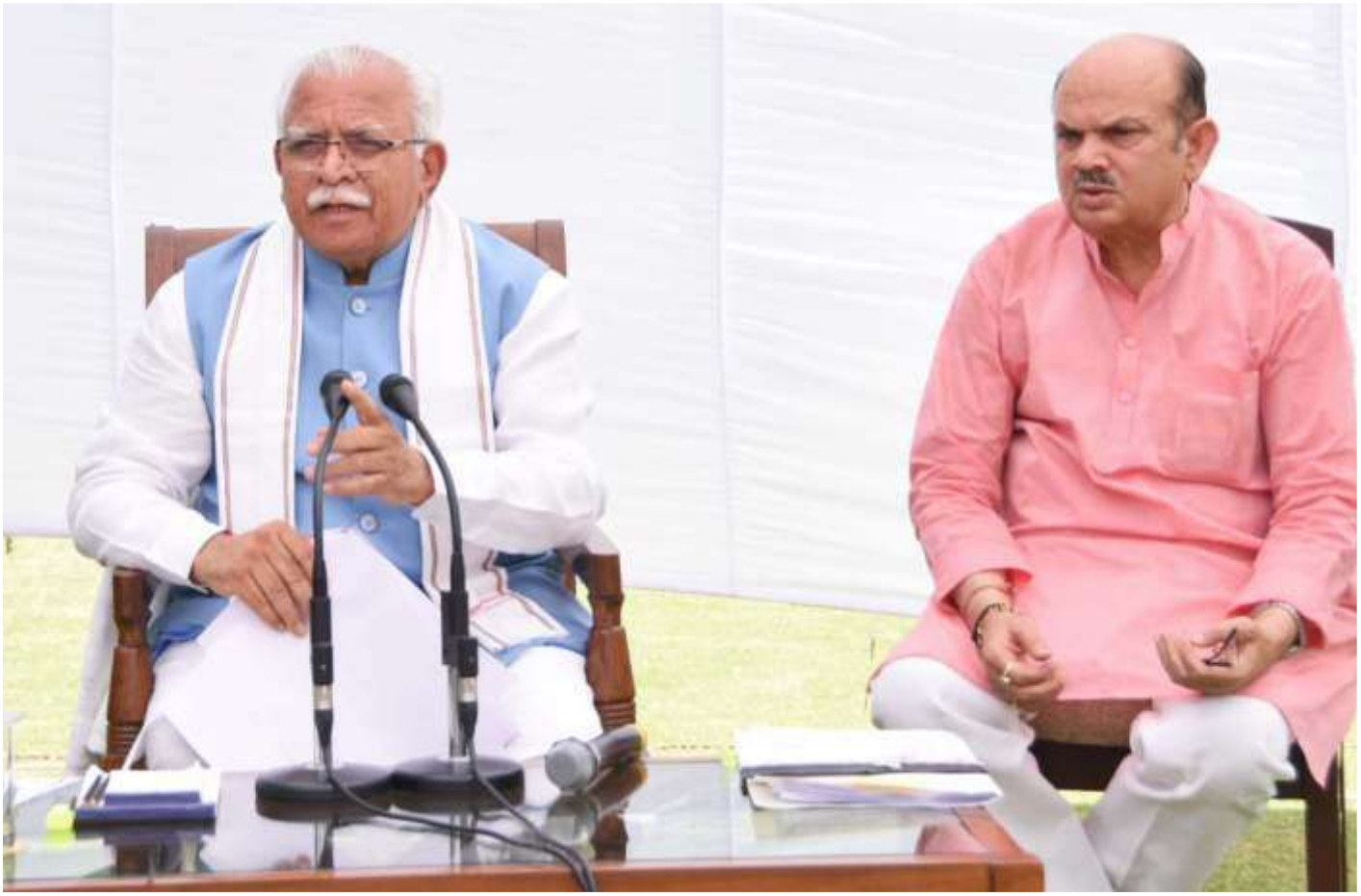

उन्होंने कहा कि प्रबुद्घ व्यक्ति या जन प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं करवाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले की यह घोषणा व्यवहार्य है या नहीं। उपायुक्त कार्यालय से भी इस सम्बन्ध में पुष्टिङ्ख की जानी चाहिए। कई घोषणायों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है जबकि अनेक बार ऐसी जमीनों के मुद्दे न्यायालय में चले जाते हैं और योजनाएं पूरी होने में विलम्बता होती है। अब ई–भूमि पोर्टल पर विकास योजनाओं के लिए भूमि खरीदने की शुरूआत की गई है। भूमि किसान की है या पंचायत की है और किस दर पर मालिक ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से बेचना चाहता है ऐसी जानकारी सब लोगों को ई–पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए।

साप्ताहिक सूचना पत्र

चंडीगढ़ में आयोजीत मिडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करना

(दिनांक 29.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पिछले साढ़े 8 साल से वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा के भाव से जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमने दिखाया है कि शासन व्यवस्था में रहते हुए एक राजनेता भी जन सेवा के कार्य कर सकता है, यह हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पौने तीन करोड़ जनता मेरा परिवार है और जनता की समस्याओं का हल करने, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है, जिससे जनता को सभी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। इसलिए पीपीपी की वास्तविक रूप से परिभाषा परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल है। पीपीपी के माध्यम से

साप्ताहिक सूचना पत्र

साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड दिसंबर के महीने में बनाए गए हैं। 2 लाख लोगों ने शिकायत की थी कि उनका गलत राशन कार्ड कट गया है। हमने सर्वे करवाया और लगभग सवा लाख राशन कार्ड दोबारा बना दिए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता कहते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो वे पोर्टल बंद कर देंगे, मैरिट वैरिट खत्म कर देंगे। लेकिन वास्तव में आम जन को हमारी सरकार की इन नीतियों से फायदा पहुंच रहा है।

इसलिए अब विपक्ष के नेताओं ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि वे जो पोर्टल अच्छे चल रहे हैं, उन्हें ऐसे ही चलने देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था तो

साप्ताहिक सूचना पत्र

क्यों किया था और आज वे नारे लगा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन को लागू करो। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को लेकर कमेटी बनाई है, जब कमेटी का निर्णय होगा आएगा तब आगे विचार करेंगे।

बेरोजगारी और सरकार पर कर्ज के आंकड़ों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष का गणित बहुत कमजोर है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार जीएसडीपी के 25 प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है और हम इस सीमा के अंदर ही हैं। कांग्रेस के समय राज्य की जीएसडीपी 3 लाख करोड़ थी, उसके हिसाब से उन्होंने ऋण लिया हुआ था। लेकिन आज प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है और हमारे प्रयासों से आज जीएसडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इस जीएसडीपी के अनुसार ही हम ऋण ले रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेरोजगारी के लिए विपक्ष एक प्राईवेट एजेंसी के आंकड़े दिखाता हैं, जिसके आंकड़े सही नहीं हैं। यह संस्था कभी 24, कभी 34 और कभी 37 प्रतिशत बेरोजगारी दर्शाती है। उसके आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर एक एक परिवार का डाटा है और इस डाटा में जो बेरोजगार हैं, उन लोगों ने स्वयं घोषित किया है। इसके अनुसार प्रदेश में लगभग 5 –6 प्रतिशत

बेरोजगारी है। इसे बेरोजगारी दर को कम करने के लिए भी लगातार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 से 18 साल तक की आयु का बच्चा भी शिक्षा से वंचित न रहे और वह चाइल्ड लेबर की ओर न जाए, इसके लिए सरकार द्वारा ड्रॉपआउट दर को कम करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल विरोध करने के लिए हमारा विरोध कर रहा है। आज जनता सब जानती है है। जनता को यह भरोसा हो गया कि वह जो भी आरोप लगाते हैं, वे गलत हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 से 18 साल तक की आयु का बच्चा भी शिक्षा से वंचित न रहे और वह चाइल्ड लेबर की ओर न जाए, इसके लिए सरकार द्वारा ड्रॉपआउट दर को कम करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज वर्तमान समय की जरूरत है। उपलब्ध जल का प्रबंधन और पानी को

रिसाइकिल कर उसका पुनरू उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मई माह में किसानों को पूरा मुआवजा मिल जाएगा। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसमेंअब किसान ही अपनी फसल के नुकसान की जानकारी स्वयं देता है इसके लिए सुरक्षा की पूर्ति पोर्टल बनाया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

फरीदाबाद में पटवारियों को टेबलेट वितरित किए गए

(दिनांक 29.04.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फरीदाबाद के एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित टेबलेट वितरण कार्यक्रम में डिजिटल सेवाओं के विस्तार को जनसेवा की दिशा में सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम में फरीदाबाद में राजस्व विभाग से जुड़े कानूनगो व पटवारियों को टेबलेट वितरित किये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से जनसेवा की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी उद्देश्य के साथ आज फरीदाबाद में ई गिरदावरी, क्षतिपूर्ति, परिवार पहचान पत्र के तहत जाति सत्यापन कार्य, इनकम वेरिफिकेशन सहित अन्य सरकारी सेवाओं का उपयोग इस टेबलेट के माध्यम से बेहतर स्वरूप से क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला के कुल 41 कानूनगो व पटवारियों को टेबलेट वितरित करते हुए उन्हें सरकारी सेवाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।